eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमः मुद्दे, चुनौतियां एवं संभावनाएं

[1] डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल,

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर –राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर (उ0प्र0)

Received: 30 june 2018, Accepted: 15 July 2018 ; Published on line: 15 Sep 2018

Abstract

भारत को एक सम्पूर्ण डिजिटल देश में बदलने के लिये भारतीय सरकार ने जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरूआत की। भारतीय समाज को सशक्त करने के लिए डिजिटल इंडिया एक योजनागत पहल है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारतीय जनता के लिये एक जनोपयोगी सेवा की तरह डिजिटल संरचना पूरे देश के लिये हो क्योंकि यह डिजिटल संरचना तेज गति से सभी को इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करायेगा। जिससे सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान और तेज हो जाएगी। ये नागरिकों को जीवन पर्यन्त, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामाणिक रूप से डिजिटल पहचान उपलब्ध करायेगा। ये किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे– बैंक खाता संभालना, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, वित प्रबंधन आदि के लिये बेहद लाभदायक सिद्ध होगा।

अतः इस पेपर के द्वारा भारतीय लोगों का डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच के बारे में बताया जायेगा। डिजिटल साक्षारता को मुमकिन किया जायेगा।

इस पेपर के द्वारा ऑनलाईन जरूरी दस्तावेज या प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए लोगों को सक्षम बनाया जायेगा।

संकेतशब्द– डिजिटल भारत, संसाधन–संशक्तिकरण–डिजिटल, संरचना–डिजिटल साक्षरता।

परिचयः

सर्वत्र विदित है कि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तब पुरानी टेक्नोलॉजी उसके सामने टिक नहीं पाती, कई बार तो अस्तित्वहीन हो जाती है। बाबर की सेना तोपें लेकर के आई तब भारत के राजे महाराजे सैनिक लाठी, भाला, धनुष बाण, लेकर उनके सामने नहीं टिक सके। अंग्रेज अत्याधुनिक बंदूकें व तोपें लेकर के आए तो मुगलों की तोपें उनके सामने नहीं टिक सकी। यानी नई तकनीक के सामने पुरानी तकनीकि आधारित वस्तुएं एवं रोजगार खतरे में पड़ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास एवं समावेशी विकास हेतु डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एप के रूप में एक महात्वाकांक्षी प्रयोग की शुरूआत की गई है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

प्रारंभ में भारत में कंप्यूटर का भी विरोध हुआ, लेकिन आज डिजिटल दुनिया के हर पल और हर दिन बदल रहे संदर्भों में कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का मुख्य अंग बन गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकारी विभागों व सभी मंत्रालयों को देश की जनता से जोड़नें की भारत सरकार की एक अंतर–मंत्रालयी पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। इसके अंर्तगत डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एवं डिजिटल साक्षरता को लक्ष्य करके योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करना है।

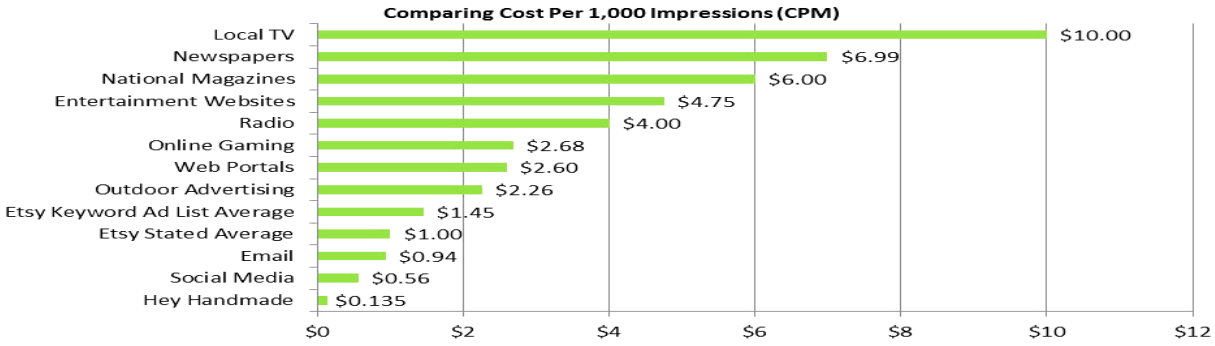

सेवा प्रदाता और उपभोक्ता को लाभ हो सके ऐसे टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी एवं भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य सभी कमियों को भी दूर करना होगा।

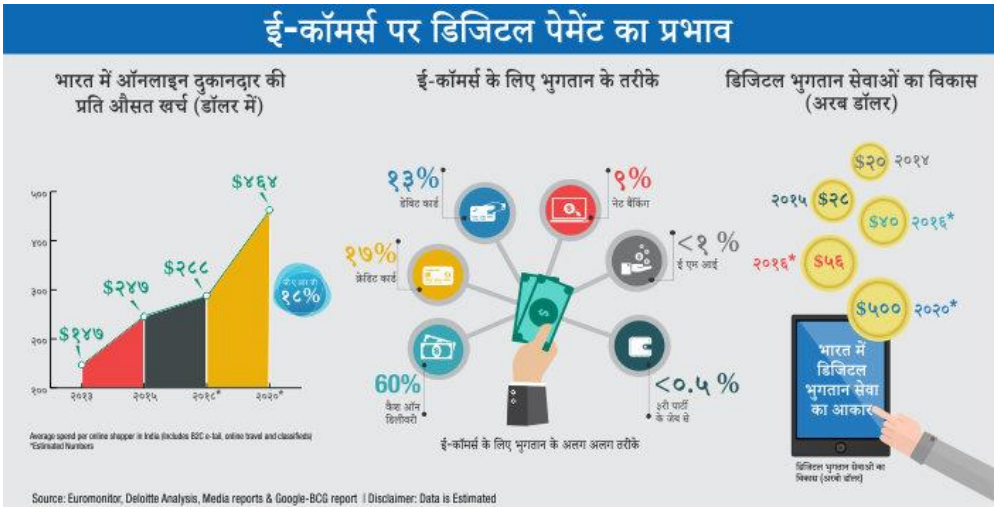

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

ब्रॉडबैंड हाईवे, सबको फोन की उपलब्धता, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, इ–शासन (टेक्नालॉजी की मदद से शासन), ई–क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं), सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी के जरिए रोजगार, भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभ हैं।

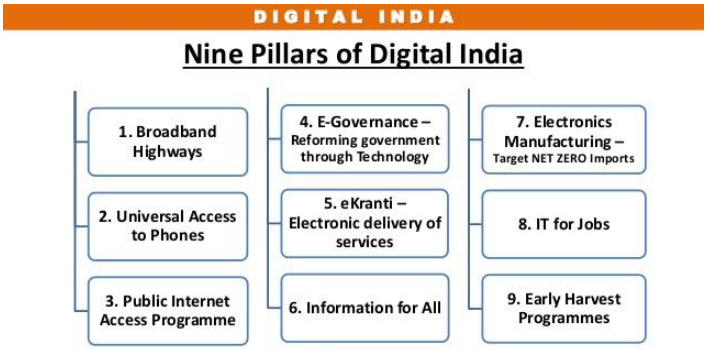

डिजिटल इंडिया योजना पर कई कम्पनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई–कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड रुपये, नई योजनाओं और गतिविधियों में, 13 हजार करोड रुपये खर्च होंगे। 2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा, 2020 तक नेट जीरो आयात, 4 लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट बनाना, 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की व्यवस्था, आमलोगों के लिए वाई–फाई हॉट स्पॉट, 1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार की संभावना सहित 1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार व 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रदान करते हुए सभी प्रदेशों में सरकारों में इ–शासन को बढावा देना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकारी विभागों व सभी मंत्रालयों को देश की जनता से जोड़नें की भारत सरकार की एक एक अंतर–मंत्रालयी पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। इसके अंर्तगत डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एवं डिजिटल साक्षरता को लक्ष्य करके योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करना है। सेवा प्रदाता और उपभोक्ता को लाभ हो सके ऐसे टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी एवं भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य सभी कमियों को भी दूर करना होगा। ब्रॉडबैंड हाईवे, सबको फोन की उपलब्धता, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, इ–शासन (टेक्नालॉजी की मदद से शासन), ई–क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं), सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी के जरिए रोजगार, भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभ हैं।

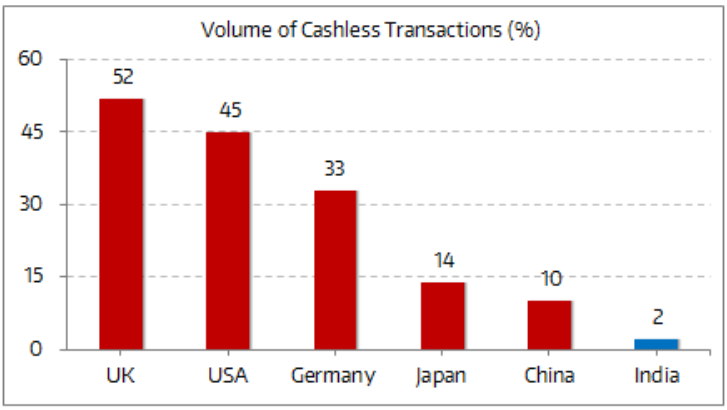

डिजिटल इंडिया योजना पर कई कम्पनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई–कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड रुपये, नई योजनाओं और गतिविधियों में, 13 हजार करोड रुपये खर्च होंगे।

2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा, 2020 तक नेट जीरो आयात, 4 लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट बनाना, 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की व्यवस्था, आमलोगों के लिए वाई–फाई हॉट स्पॉट, 1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार की संभावना सहित 1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार व 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रकान करते हुए सभी प्रदेशों में सरकारों में इ–शासन लागू करना है।

विश्वभर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें फेसबुक, ट्वीटर, आर्कुट, माई स्पेस, लिंक्डइन, फ्लिकर, इंस्टाग्राम (फोटो, वीडियो शेयरिंग साइट्स) सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। एक सर्वे के मुताबिक विश्वभर में संप्रति 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स (फेसबुक इस्तेमाल करने वाले) हैं। वहीं, विश्वभर में इंस्टाग्राम यूजरों की संख्या 15 करोड़, लिंक्डइन यूजरों की संख्या 20 करोड़, माई स्पेस यूजरों की संख्या 3 करोड़ और ट्वीटर यूजरों की संख्या 9 करोड़ है।

हमारे लिए काफी उपयोगी है, इसके द्वारा मित्र–रिश्तेदारों से कम्यूनिकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज फेसबुक के जरिये लगभग 50 मिलियन लोग अपने ब्रांड को काफी कम कीमतों में एक सफल कस्टमर बेस तक पंहुचा रहे हैं।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

इधर, कम उम्र के बच्चों ने भी फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिसका उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले दिनों ऐसोचौम की ओर से किये गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक, जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 73 प्रतिशत बच्चों की उम्र 8 से 13 साल (13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध है) के बीच है। सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरीपेशा हैं और वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं लिहाजा ये बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर मशगूल रहने लगे हैं क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें एक ऐसा समाज देता है।

जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के अधिक इस्तेमाल से छात्रों की पढाई पर बुरा असर होता है। खासकर फेसबुक से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है और उनका रिजल्ट तक खराब हो जाता है। फेसबुक का अधिक इस्तेमाल करने वाले दिन भर अपने मोबाइल या लैपटाप से चिपके हीं है।

आज स्मार्ट फोन का जमाना है और युवाओं की इस तरफ तेजी से बढ़ती दिलचस्पी का मुख्य कारण वॉट्सएप है। हर कोई वॉट्सएप पर आना चाहता और अपने सर्कल से जुड़े रहना चाहता है। वॉट्सएप एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसने आज एसएमएस की सुविधा को पीछे छोड़ दिया है। कनेक्टेड रहने और अपनी बाते शेयर करने का बहुत बड़ा माध्यम आज वॉट्सएप है। आप अपने दोस्तों से फोटो, वीडियो, म्युजिक, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। यह ऐप आपके फोन के कॉन्टैक्ट को अपने आप इम्पोर्ट करता है और आपको बताता है कि आपके कितने फ्रेंडस वॉट्सएप यूज कर रहे हैं।

आप विश्व के किसी भी कोने में किसी को भी फ्री में मैसेज भेज सकते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बस आपके फोन में वॉट्सऐप होना चाहिए और जिसे मैसेज भेजना चाहते हैं वह भी वॉट्सएप पर होना चाहिए और फिर आप अंतरराष्ट्रीय मैसेज भी कर सकते हैं। आपको चौटिंग और शेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।बस आपके फोन में इंटरनेट पैक होना जरूरी है। आप करीबन 50 लोगों का ग्रुप भी बना सकते हैं जहां आप सभी लोगों से साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और जरुरी जानकारी एक साथ पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई अंजान व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आप उसको अपने वॉट्सएप से ब्लॉक भी कर सकते हैं।

हर एक को मैसेज करने के बजाये क्लास या बिजनेस का ग्रुप बनाकर एक ही जगह मैसेज करके सबको साथ में सूचना दी जा सकती है। इसके सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, कई मायनों में यह नुकसानदायक भी है जैसे वॉट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपको कोई भी एड कर सकता है अगर उसके पास आपका नंबर हो। आप अनचाहे ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। कई बार ग्रुप में एक साथ बहुत सारे मैसेज आने की वजह से जरुरी जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार आपका लास्ट सीन रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। वॉट्सएप से डिस्ट्रेक्शन होता है क्योंकि आप उसे बार–बार चेक करते हैं।

सोशल मीडिया की पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें ट्विटर की भूमिका अहम है। ट्विटर के माध्यम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर भी लोग सीख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ट्विटर की उपयोगिता सिलेब्रेटीज के लिए अधिक है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं,

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

वे कब क्या कर रहे हैं और इसीलिए ट्विटर पर सेलेब्रिटीज के फॉलोअर बहुत बड़ी संख्या में हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस भी सेलेब्रिटीज के ट्विटर पेज को इसीलिए फॉलो करते हैं कि उनके बारे में त्वरित जानकारी मिल सके। इसकी पहुंच लगातार बढ़ती ही जा रही है। मदद से जानी मानी हस्तियाँ आसानी से अपने फैन्स और फॉलोअर्स रूबरू हो सकती हैं। ट्विटर की मदद से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुडे रह सकते हैं। यह देश विदेश की किसी भी जानकारी को त्वरित प्राप्त करने का आसान माध्यम है। प्रचार करने के लिये ट्विटर एक बड़ा माध्यम है।

ट्विटर के बारे मे ज्यादा जानकारी न होने के कारण अकसर लोग वेरीफाइड खाते नहीं पहचान पाते हैं। ट्विटर के अगर कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं जैसे शब्द सीमा होने की वजह से भी लोग ट्विटर को इस्तेमाल करने से कतराते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी बात संक्षिप्त में समझा नहीं सकता। ट्विटर एक वक्त के बाद काफी नीरस लगने लगता है। ट्विटर में यूजर को हर ट्विट से गुजरना ही होता है। ट्विटर से आसानी से भ्रम फैलाया जा सकता है।

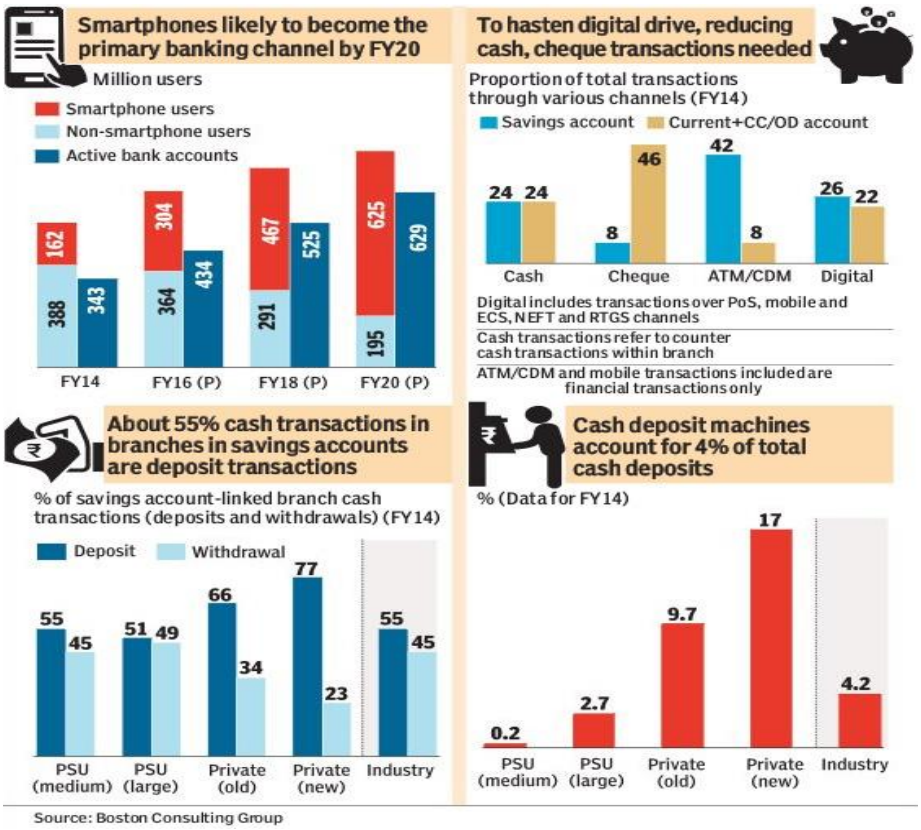

भारत सरकार के ई–गवर्नेस कार्यक्रम के स्थान पर ई–क्रांति के सिद्धान्त को अपनाया जा रहा है। ई–क्रान्ति के तहत विभिन्न सेवाओं में बदलाव, निजी सुविधाओं को सुदृढ़ करना, सुरक्षा तथा इलेक्ट्रानिक डेटा का संरक्षण, प्रत्येक भाषा का स्थानीकरण, गवर्नमेंट प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, आधारित अवसंरचना का विकास, मोबाइल एप द्वारा शिकायत की प्रक्रिया को तीव्र गति से व्यवहार में लाया जाना आदि है। डिजीटलीकरण की पारदर्शिता के कारण ही सुरक्षा की दृष्टि से डायल 100 (तत्काल पुलिस का पहुँचना) तथा पीड़ित के मोबाइल नं0 पर सूचना तथा कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सिस्टम का

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

एकीकृत होना, न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्याय पालिका भी डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अपना रहा है ताकि लोगो को उच्च स्तर की सुविधा प्रदान की जा सके।

सरकार तमाम समाजिक एवं कल्याणकारणी कार्यक्रमों में आधार प्रणाली एवं बायोमैट्रिक तकनीकी का प्रयोग कर रही है ताकि फर्जीवाड़ी को समाप्त किया जा सके एवं एक स्वच्छ तथा पारदर्शी समाज की स्थापना की जा सके। भारत में राशन कार्ड के निर्माण में, स्च्ळ सब्सिडी धारको के चयन में, प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक अनियमितता पायी गई है। जो डिजिटलीकरण के द्वारा पकड़ में आया है। डिजिटलीकरण के द्वारा बिचौलियों की संख्या में कमी आयी है तथा समाज में जागरूकता एवं स्वच्छ प्रशासन के कारण लोगों में विश्वास (सरकार के प्रति) बढ़ा है।

भारत में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से मात्र 33ः ही स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके 2019 तक बढ़कर 40ः तक होने की संभावना है। बिजली डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 22ः ग्रामीण घरों में आज भी बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की तो लगभग आधी ग्रामीण आबादी विद्युत सुविधाओं से वंचित है। एसोचौम की एक रिपोर्ट के अनुसार 19ः भारतीय आबादी आज भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर और वित्तीय रूप से बहिष्कृत है। ई–वालेट या अन्य डिजिटल पेमेंट के तरीकों से भुगतान के लिये व्यक्ति का एक क्रियाशील बैंक–खाता, इंटरनेट की सुविधा वाला मोबाइल फोन या क्रेडिट–डेबिट कार्ड होना चाहिये।

डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना की अपर्याप्तता, जैसे–बिजली, ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं की कमी आदि। भुगतान के लिये ग्रामीण आबादी नकद पर जितना विश्वास करती है और उसके इस्तेमाल में सहज होती है, उतनी सहज वह डिजिटल भुगतान तकनीकों के प्रति नहीं होती। इसके पीछे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी एक कारण है। भारत की ग्रामीण आबादी डिजिटल रूप से अशिक्षित है। डिजिटल व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने और संप्रेषित करने तथा नई तकनीकों के प्रति अज्ञानता डिजिटल ग्रामीण भारत की राह में बाधा है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र से संबंधित है, जिसके संचालन के लिये नकद का उपयोग डिजिटल भुगतान की बजाय ज्यादा आसान होता है। देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायतों व अन्य धार्मिक समूहों द्वारा महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना आम बात है। ळैड।–रिपोर्ट 2016 (शीर्षक–कनेक्टेड वूमन) के अनुसार भारत में 72ः महिलाएँ मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करती हैं। स्टैटिस्टा नामक पोर्टल के अनुसार शहरी भारत में मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली 38ः महिलाएँ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यह आँकड़ा मात्र 12ः है।

भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एप्प एवं पोर्टल जनता की भलाई के लिए जारी किया गया है, जो निम्नलिखित हैं–

1– **भीम एप्प** (**Bharat Interface for Money) –** इसके द्वारा घर बैठे इण्टरनेट के माध्यम से लेन–देन किया जा सकता है बिना बैंकों के चक्कर लगाये।

2– **डिजिलॉकर** (**Digitally Empowered Society and Knowledge Economy)–** यह एक प्रकार से सूचनाओं एवं जानकारियों का भंडार है। इसमें सभी प्रकार सूचनाओं एवं जानकारियों का भंडार

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

किया जाता है,जिससे भविष्य में जब भी जरूरत पड़े इसे देखा जा सकता है, जैसे– सभी प्रकार के डाक्यूमेंट तथा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,जन्म प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र, खसरा–खतौनी आदि।

3– **ई–पंचायत–** इसके अन्तर्गत पंचायती राज से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।

4–**ई–डिस्टिक्ट–** एक जिले से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आनलाइन देखी जा सकती है।

5–**ई–हास्पिटल–** चिकित्सालय एवं चिकित्सा से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां।

6– **निर्भया एप्प–** लड़कियों तथा महिलाओं के यौन–शोषण एवं छेड़छाड़ से बचाव हेतु जानकारियां।

इनके अतिरिक्त **एम–किसान,नेशनल नालेज नेटवर्क, नेशनल स्कालरशिप पोर्टल, पहल एप्प, परिवहन पोर्टल, ई–पाठशाला, ई–नाम, ई–साइन, ई–वीजा, जी0आई0एस0** आदि पोर्टल एवं एप्प जनता की जानकारी तथा सेवाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु सरकार ने जारी किए हैं, जिससे सरकारी कामकाज से संबंधित जानकारियां शहर हो या गांव के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुॅचे, जिससे वह उसका लाभ उठा सकें। बिचौलिए, दलालों एवं इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का यह सबसे बेहतर तरीका है।

डिजिटलीकरण के लाभ–

1– डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम से सभी को सही तरह से लाभ हो रहा है।

2– रिश्वतखोरी की आदत एवं व्यवहार को जबरदस्त झटका लगा है। आर्थिक भृष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिल रही है।

3– कागजीराज को खत्म किया जा रहा है। सारे कामकाज आनलाइन होने लगे हैं। जिसके परिणामस्वरूप कागजी खर्च को समाप्त किया जा रहा है। सरकारी विभागों, दफ्तरों तथा कार्यालयों में लेटलतीफी, टाल–मटोल तथा विलम्ब करने का युग समाप्त हो रहा है।

4– हर व्यक्ति को सही, सटीक और तीव्र गति से सभी जानकारियॉ मिल रही है। सरकारी विभागों तथा दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे है।

5– डिजिटलीकरण का पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि यह प्रोगाम पर्यावरण के अनुकूल है। एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है।

चुनौतियां–

1– तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है या इसके प्रगति की गति बहुत धीमी है, जैसे– रेलवे स्टेशन तथा कई अन्य सरकारी विभाग हाई–स्पीड ब्राडबैंड से अभी तक लैस नहीं हो पाये हैं। गावों में हाई–स्पीड ब्राडबैंड के प्रसार का नितांत अभाव है।

2– तकनीकी शिक्षागरीबी और मंहगाई के चलते गरीब एवं निरक्षर व्यक्ति इसका लाभ लेने से वंचित हैं।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

3– बच्चों पर इन तकनीकों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

4– साइबर अपराध तथा सूचनाओं की चोरी को रोकने के लिए सख्त कानूनों की कमी है।

5–आतंकवादियों एवं अपराधियों द्वारा इन तकनीकों का इस्तेमाल आतंक, विध्वंस, डाटा चोरी तथा अवैध तरीके से फंडिंग करने में किया जा रहा है। यह सब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिससे समय रहते तुरंत निपटने की जरूरत है।

परिकल्पनायें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक प्रयास के अन्तर्गत कतिपय निम्नलिखित परिकल्पनायें रेखांकित की जा सकती हैं–

1– संपूर्ण देश पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि देश के वे भाग, जहाँ पर जन जागरूकता अधिक है, अपेक्षाकृत नागरिकों को सेवायें मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाईस्पीड इण्टरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

2– डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्‌गम स्थल जो अनोखा हो, ऑन लाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य हो, मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तियन मामले में नागरिकों की भागीदरी हो सकें, साझा सेवा केन्द्र तक आसान पहुॅच सुनिश्चित होगी।

3– पब्लिक क्लॉउड पर साझा करने योग्य नीजि स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस, सभी विभागों और न्यायालयों की मॉग पर समेंकित सेवाओं सहित शासन एवं सेवायें उपलब्ध करवाना, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरिकों को क्लाउड एप्प पर उपलब्ध रहने का अधिकार हो, डिजिटल तब्दील सेवाओं के जरिये व्यवसाय में सहज बनाने का अधिकार हो, इलेक्ट्रानिक और नगदी रहित वित्तिय लेन–देन करने की सुविधा हो, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए जी.आई.एस. का लाभ उठाना शामिल हो, नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ ही सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता हो, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधन उपलब्ध हो, डिजिटल संसाधनों एवं सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता आदि सुनिश्चित हो सकेगा।

4– सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म और पोर्टबिलिटी के सभी अधिकारों को क्लाउड के जरिये सहयोगपूर्ण बनाना।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

5– नागरिकों को शासकीय दस्तावेजों या प्रमाण–प्रत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जा सकेगा।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूची विधि और निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन संबंधी द्वितीय तथ्यों को विभिन्न शोध प्रबंधों, गजेटियर, शोध पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों से डेटा एकत्रित्र व प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। यह शोध–पत्र पुस्कालय अध्ययन पद्धति पर आधारित है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

यदि इस लेख का परिणाम या निष्कर्ष केवल एक वाक्य में कहें तो नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से डिजीटल क्षेत्र में साक्षर बनाना है और डिजीटल सशक्तिकरण होने के बाद कागजी काम कम हो जायेगा जैसे जमीन जायदाद का बैनामा, अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइन्टमेंन्ट, ओ0पी0डी0 की जानकारी, ई–लॉकर, ई–बस्ता, छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जनरेसन नेटवर्क का प्रयोग, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ पुलिस स्टेशन, अस्पताल पर सीसीटीवी कैमरे तथा डाटा अपडेट होंगे इसके साथ शैक्षिक संस्थानों को वाई फाई हॉट स्पॉट से अपडेट करेंगे, कॉल सेन्टरों की संख्या बढेगी जिससे रोजगार भी बढेगा।

लोगों के दस्तावेजों जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्रों पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि का डिजीटल स्टोर करना इसके साथ ही भारत के सभी दूर दराज एवं पहाडी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर अनिवार्य होने से पूरे भारत में ई–गवर्नेंस की व्यवस्था होगी, लेकिन भारत को डिजीटल भारत बनाने में इस टैक्नोलॉजी की कुछ कमियॉ जैसे गोपनीयता की कमीं, नागरिक स्वायतता हनन, ई– सर्विलान्स हेतु संसदीय निगरानी की कमी, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी के साथ–साथ साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियॉ हैं, डिजीटल भारत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करते हुए प्रत्येक नागरिक को डिजीटल टैक्नोलॉजी में साक्षर बनाना है, जिससे देष का प्रत्येक नागरिक देष के विकास में अपना योगदान दे सकें। डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये।

क्षेत्रीय भाषा से संचालित होने वाले तथा कम लागत में विशेष रूप से तैयार किये गए मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल–व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

अबाधित बिजली–आपूर्ति, सस्ती इंटरनेट–कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण भारत न केवल डिजिटल रूप से साक्षर होगा, बल्कि उसका सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी संभव हो सकेगा। संस्थागत ऋण की व्यवस्था, JAM–ट्रिनिटी के उचित क्रियान्वयन से तथा भू–आलेखों के डिजिटलीकरण आदि के द्वारा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को अनौपचारिक से औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है।

डिजिटल भुगतान आदि के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिये सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी चाहिये। एक सुरक्षित साइबर–स्पेस ग्रामीणों को डिजिटल व्यवहार के लिये प्रेरित करेगा। व्यापारिक गतिविधियों के दौरान डिजिटल भुगतान के लिये दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर POS- मशीनों (पॉइंट ऑफ सेल) आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिये इस योजना में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जिससे 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के साथ ग्रामीण भारत में काम करने वाले 8.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और तकरीबन 18 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल साक्षर बनाकर लगभग पूरी ग्रामीण आबादी तक डिजिटलीकरण की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

डिजिटलीकरण उत्पादन और वितरण प्रक्रिया में सुधार लाता है और आर्थिक–विकास को गुणात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन डिजिटल इंडिया जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वाले अभियान तभी सफल होंगे, जब भारतीय अर्थव्यवस्था मे रहने वाले निचले स्तर पर अर्थात् ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से साक्षर न बना दिया जाए। साथ ही ग्रामीण भारत का आर्थिक रूप से भी इतना सक्षम होना जरूरी है कि डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक उपकरणों तक उसकी आसान पहुँच बन सके। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच के डिजिटल डिवाइड को कम करके ही देश में शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। अतः विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई अनेक पहलें न केवल समाज में क्रांति लाने का एक प्रयास है बल्कि शोषितों को ऊपर उठाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देना है ताकि विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच विषमता को खत्म किया जा सके। अनेंकों चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह समय की मॉग तथा वक्त की जरूरत है। इससे न केवल काम–काज

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

में तीव्रता, गति एवं पारदर्शिता आती है बल्कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा विलम्ब से भी बचा जा सकता है।भारतीय अर्थव्यवस्था को कागजलेस और कैशलेस बनाकर कागजी राज एवं इंस्पेक्टरराज की शोषणमूलक व्यवस्था को समाप्त करके एक आधुनिक तकनीकयुक्त अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है। हॉ इसके लिए कानूनों एवं नीतियों को थोड़ा और सख्त बनाना होगा। डिजिटल साक्षरता को और प्रभावी करना होगा तथा जनता को भी सरकार की इस मुहिम में साथ देना होगा। तब निश्चित रूप से भारत न केवल एक विकसित औगोद्यिक राष्ट्र बन सकेगा, बल्कि एक विकसित तकनीकयुक्त डिजिटल इण्डिया भी बन सकेगा।

सुझाव

☐ सरकार का लक्ष्य है सबके पास फोन की उपलब्धता, जिसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास फ़ोन खरीदने की क्षमता हो. ख्याल अच्छा है, लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि क्या सबके पास फोन खरीदने की क्षमता आ गई है। या फिर सरकार अगर ये सोच रही है कि वो खुद सस्ते फोन बनाएगी तो इसके लिए तकनीक और तैयारी की जाए।

☐ ब्रॉडबैंड हाइवे के तहत देश के आख़िरी घर तक ब्रॉडबैंड के ज़रिए इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि नेशनल ऑप्टिक फ़ाइबर नेटवर्क का प्रोग्राम, जो तीन–चार साल पीछे चल रहा है। सरकार को ये समझना होगा कि जब आप गांव–गांव तार बिछाने जाएंगे तो आप उन लोगों को ये काम नहीं सौंप सकते जो पिछले 50 साल से कुछ और बिछा रहे हैं। आपको वो लोग लगाने होंगे जो ऑप्टिक फ़ाइबर नेटवर्क की तासीर समझते हैं।

☐ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम अर्थात हर किसी के लिए इंटरनेट हो यह अच्छी बात है। इसके लिए पीसीओ के तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाए जा सकते हैं। ये पीसीओ आसानी से समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन हर पंचायत के स्तर पर इसको लगाना और चलाना कोई आसान काम नहीं है क्योकि इसी के चलते विगत कई साल से योजना लंबित है।

☐ ई–गवर्नेंस अर्थात सरकारी दफ्तरों को डिजीटल बनाना और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का अर्थात इसे लागू करने का पिछला अनुभव बताता है कि दफ्तर डिजीटल होने के बाद भी उनमें

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

काम करने वाले लोग डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं। इसका तोड़ निकालने का कोई नया उपाय सरकार को ढूंढना होगा।

☐ ई–क्रांति अर्थात ई–गवर्नेंस से जुड़ा मसला और सरकार की मंशा है कि इंटरनेट के ज़रिए विकास गांव–गांव तक पहुंचे। लोगों को लगता है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ई–क्रांति के लिए हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा प्रशिक्षण और उपकरण सबकुछ डिजिटल होना ज़रूरी है। अगर हमने सरकार के ढांचे को इंटरनेट से नहीं जोड़ा तो फिर इसके तहत डिलीवरी कैसे करेंगे? और अगर कर भी दी, तो सही में इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है। फिलहाल इसमें बड़ी धांधली व दिक्कत होती है।

☐ इंफ़ोर्मेशन फ़ॉर ऑल यानी सभी को जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन अक्सर प्रश्न उठता है कि एक्सेस टू इंफ़ॉर्मेशन के अभाव में यह कैसे संभव है? इसके लिए ज़रूरी है अच्छा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि लोग आसानी से जानकारियां पा सकें। साथ ही इसके तहत सिर्फ सूचनाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है या ज़मीनी सूचनाएं इक्ठठी करना भी है। अगर सिर्फ पहुंचाना मकसद है तो यह गैर–लोकतांत्रिक है।

☐ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के तहत डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल–पुर्जों के आयात को शून्य करना है। यह कभी भी संभव नहीं है क्योंकि वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती है, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन का सवाल है तो अभी तक हम इस मामले में शहरों तक ही सीमित हैं और गांवों तक जा ही नहीं रहे हैं। इसमें नीति और नियमितता की चुनौतियां बहुत ज्यादा है।

☐ आईटी फ़ॉर जॉब्स (रूरल बीपीओ) सरकार अगर आईटी क्षेत्र के ज़रिए नौकरियां पैदा करना चाहती हैं तो हर ब्लॉक स्तर पर हमें रूरल बीपीओ खोल देना चाहिए। रुरल बीपीओ प्रोग्राम से रोज़गार के अवसर भी बनेंगे, डिजिटाइजेशन और ई–गवर्नेंस भी होगा। ये काम भी पिछले कई साल से लंबित है और ड़िजीटल क्रांति के मार्ग में मे एक बडी बाधा है।

☐ ड़िजीटल क्रांति के लिए जहां तक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम की बात है यह लक्ष्य अभी तक बिलकुल समझ नही आ पा रहा है, मोटे तौर इसका संबंध दफ्तरों और स्कूल–कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाज़िरी से है, लेकिन सरकार इसके ज़रिए क्या करना चाहती है ये जानना ज़रूरी है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

लेकिन अहम बात यह है कि क्या हम अपनें उद्देश्यों को पुराने दिमाग से चला रहे हैं। अगर वही ईंट–पत्थर तोड़ने वाले राज–मिस्त्री ज़मीनी स्तर पर इसके लिए काम करेंगें तो क्या काम हो पाएगा? और अगर हम इसे नई सोच के तहत करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पूरी तरह से नया रवैया अपनाना पड़ेगा।

☐ ड़िजीटल क्रांति को लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में लेना होगा तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं में इसे शामिल करते हुए सुशासन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। एक बड़ा मुद्दा है इसलिए ड़िजीटलीकरण सम्बन्धी जो भी नीति बनायी जाये वह उचित, समग्र और उपयोगी होनी चाहिए। इस अभियान पर जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को देश में हर शहर और गांव के लिए समेकित योजना बनानी पड़ेगी साथ ही इसके लिए बहुत अधिक धनराशि भी खर्च करनी पड़ेगी। हम सभी एक पारस्परिक निर्भर समाज में रह रहे है तथा सभी एक दूसरे से जुड़े है। इसलिए सरकार, सिविल सोसाइटी और समाज के विभिन्न वर्गो को इस अभियान का लक्ष्य पाने के लिए मिल जुलकर कार्य करना होगा।

☐ सिर्फ अभियान शुरु करना ही काफी नहीं है यह पहले भी चलाए जा चुके हैं, परिणाम मायने रखता है। सिर्फ सरकार इसे सफल नहीं बना सकती, इसमें लोगों की भागीदारी सबसे आवश्यक तत्व है। इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत ब्लू प्रिंट बनाने की आवश्यकता है। अभियान को सफल बनानें हेतु देश के नागरिकों को सरकार एक टोल फ्री नंबर प्रदान करे ताकि नागरिक इस विषय पर अपनी शिकायतें एवं सुझाव सरकार तक पहुंचा सकें।

☐ देश के समस्त नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता हेतु डिजिटलीकरण से भारत में कागजीराज को खत्म किया जा सकता है। जिससे सारे कामकाज आनलाइन हों व कागजी खर्च को समाप्त किया जा सके। सरकारी विभागों, दफ्तरों तथा कार्यालयों में लेटलतीफी, टाल–मटोल तथा विलम्ब करने का युग समाप्त हो सकता है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र मे अभी और कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

☐ नवीन तकनीकी प्लेटफॉर्म और परियोजनाओं हेतु लोगों के दस्तावेजों जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्रों पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि का डिजीटल स्टोर करना इसके साथ ही भारत के सभी दूर दराज एवं पहाडी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर अनिवार्य होने से पूरे भारत में ई–गवर्नेंस की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

☐ कौशल विकास के माध्यम से रोजगार समृद्धि हेतु सामाजिक नवाचार द्वारा प्राप्त अनुशंसित सुझाव बड़े पैमाने पर लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाएं इसके लिए अनवरत प्रयास की आवश्यकता है। इस अभियान से कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले खर्च में कटौती करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे विभिन्न अन्य नवीन क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा होंगी।

☐ ई शासन और मांग के अनुरुप सेवाएँ हेतु डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषा से संचालित होने वाले तथा कम लागत में विशेष रूप से तैयार किये गए मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल–व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अबाधित बिजली–आपूर्ति, सस्ती इंटरनेट–कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण भारत न केवल डिजिटल रूप से साक्षर होगा, बल्कि उसका सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी संभव हो सकेगा। इस दिशा में अनेक ठोस कदम को उठाये जाने की आवश्यकता है।

☐ सशक्त समाज का निर्माण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हेतु डिजिटल भुगतान आदि के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिये सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी चाहिये। एक सुरक्षित साइबर–स्पेस ग्रामीणों को डिजिटल व्यवहार के लिये प्रेरित करेगा। व्यापारिक गतिविधियों के दौरान डिजिटल भुगतान के लिये दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर च्वै. मशीनों (पॉइंट ऑफ सेल) आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

☐ नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से डिजीटल क्षेत्र में साक्षर बनाए जाने की आवश्यकता है, डिजीटल सशक्तिकरण होने के बाद कागजी काम कम हो जायेगा– जैसे जमीन जायदाद का बैनामा, अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइन्टमेंन्ट, ओ0पी0डी0 की जानकारी, ई–लॉकर, ई–बस्ता, छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जनरेसन नेटवर्क का प्रयोग, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ पुलिस स्टेशन, अस्पताल पर सीसीटीवी कैमरे तथा डाटा अपडेट होंगे इसके साथ शैक्षिक संस्थानों को वाई फाई हॉट स्पॉट से अपडेट करेंगे, कॉल सेन्टरों की संख्या बढेगी जिससे रोजगार भी बढेगा।

☐ डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषा से संचालित होने वाले तथा कम लागत में विशेष रूप से तैयार किये गए मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल–व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अबाधित बिजली–आपूर्ति, सस्ती

इंटरनेट–कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण भारत न केवल डिजिटल रूप से साक्षर होगा, बल्कि उसका सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी संभव हो सकेगा। संस्थागत ऋण की व्यवस्था, श्र।ड–ट्रिनिटी के उचित क्रियान्वयन से तथा भू–आलेखों के डिजिटलीकरण आदि के द्वारा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को अनौपचारिक से औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है।

☐ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिये इस योजना में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिससे 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के साथ ग्रामीण भारत में काम करने वाले 8.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और तकरीबन 18 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व प्राथमिक शिक्षकों को डिजिटल साक्षर बनाकर लगभग पूरी ग्रामीण आबादी तक डिजिटलीकरण की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

अंततवोगत्वा ड़िजीटल क्रांति को लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में लेना होगा तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं में इसे शामिल करते हुए सुशासन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा।

सन्दर्भः

1- अजय कुमार, डिजीटल इंडिया, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, 2018
2- प्रदीप ठाकुर, भारत मे डिजीटल क्रान्ति, प्रभात पब्लिकेशन नई दिल्ली,2018।
3- डिजीटल इंडिया, वार्षिक रिर्पोटः2017–18, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय,भारत सरकार।
4- कुरूक्षेत्र पत्रिका, अगस्त 2017, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली।
5- pibindia.wordpress.com डॉ0 गुरमीत सिंह,भारत मे डिजीटल क्रान्ति।
6- Gupta, N., & Arora, K. (2015). Digital India: A Roadmap for the Development of Rural India. International Journal of Business Management, 2(2), 1333-1342
7- Goswami, H. (2016).Opportunities and Challenges of Digital India Programme. International Education and Research Journal, 2(11), 78-79.
8- www.digitalindia.gov.in
9- http://pib.nic.in/newsite/Print Release.aspx?relid=108926

10- वित्त मंत्रालय की वेवसाईट, भारत सरकार ।

11- कुरूक्षेत्र सितम्बर 2015 ।

12- योजना अंक जनवरी, अक्टूबर, 2015

13- वाटर एड इंडिया (2008) तिरुचिरापल्ली शोज द वे

14- कुरूक्षेत्र अंक अक्टूबर, 2014

15- https://iasscore.in/national-issues/digital-india-programme-importance-and-impact, date- 29/08/2018,04:02pm.

16- 2- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India,28/08/2018,11:25am.

17- 3- https://www.quora.com.

18- 4- https://www.mygov.in/group/digital-india

19- 5- https://www.thebetterindia.com

20- 6- http://negd.gov.in

21- ik.Ms;] jfoizdk"k ¼2012½ % oS"ohdj.k ,oa lekt] okjk.klh fot; iz0 eafnjA

22- 2- HkkxZo] xksiky ¼2004½ % ekl ehfM;k ,.M ifCyd b";wt] bZ"kk cqDl] fnYyhA

23- 3- fMftVy bf.M;k % fodhihfM;k] Ýh bUlkbDyksihfM;kA

24- 4- fMftVy bf.M;k % buhfl;sfVo lk¶Vos;jA

25- 5- VsDukykWth ikdZ bu bf.M;k % fn bf.M;u ,Dlizsl] 28 Qjojh 2016

26- 6- fMftVy bf.M;k % http://www.digitalindia.gov.in//

27- 7- vfer izdk"k % fMftVy bf.M;k uhM~l Vw xks yksdy Mobile Google.com, www.khayalrakha.com

28- 8- https://googleeweblight.com//174 - Oct. 25, 2017

29- 9- Slogans : www.hindiaslogans.com/201

30- 10- ,l0 izdk"k vk;Z % iks,e & globepoems.biogel.

31- 11- fot; dqekj % fMftVy Hkkjr https://googleweblight.com

32- 12- fMftVy bf.M;k izksxzke % pdf. Sept. 23, 2017, google